

सम्पादकीय

**आबादी का स्वरूप बिगाड़ती
घुसपैठ, राज्यों के सहयोग
के बिना इसपर नियंत्रण**

पाना असंभव

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक हुई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष हैं तो बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तो मौजूद रहे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं भाग न लेकर अपनी जगह उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भेजा। इसी तरह का एक और वाक्य देखिए। कुछ समय पहले कोलकाता में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 'पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद' की एक बैठक हुई। इसमें सीमा पार यानी बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ और तस्करी आदि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री के अलावा बंगाल और झारखण्ड के मुख्यमंत्री तो शामिल हुए, पर ओडिशा और बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। जबकि बिहार इन दिनों 'जिहादी आतंकवाद की शरणस्थली बना हुआ है। देश को पांच क्षेत्रों-उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण में विभाजित किया गया है। दरअसल अंग्रेजी शासन के तहत बिहार बंगाल, ओडिशा और

बिहार, बंगाल, आडिशा और झारखण्ड एक ही प्रांत थे। इसे ही 'पूर्वी भारत' भी कहा जाता है। चारों प्रांतों की सीमाएं अनेक जगहों पर आपस में मिलती हैं। बंगाल और बिहार ही पूर्वोत्तर के आठों प्रांतों को भारत से जोड़ते हैं। अतः सामरिक दृष्टि से इनका अपना एक विशेष महत्व है। बांगलादेश की आधी यानी लगभग 2,200 किलोमीटर की सीमा बंगाल से सटी हुई है। बांगला भाषा के कारण भारतीय और बांगलादेशी के बीच फर्क कर पाना कठिन होता है। इसका फायदा उठाकर बांगलादेश से घुसपैठि, आतंकी और तस्कर भारत में प्रवेश करते रहे हैं। 1979 में असम के मंगलदोई संसदीय सीट पर पुनर्मतदान के समय मात्र एक वर्ष में ही लगभग 47,000 मुस्लिम मतदाताओं की वृद्धि ने बांगलादेश से हो रही इस घुसपैठ के प्रति देश का ध्यान खोंचा। मुस्लिम घुसपैठ के कारण असम में चले आंदोलन और फिर केंद्र सरकार एवं असम आंदोलनकारियों के बीच रहा ज़िरखड़ में हैदूर जनसंख्या वृद्धि दर 142.21 तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 340.35 प्रतिशत रही। झारखण्ड के संताल परगना के साहिबगंज में 14.7 प्रतिशत तो पाकुड़ जिले में मुस्लिम जनसंख्या में 13.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिहार के किशनगंज प्रखण्ड में मुस्लिम आबादी 14.19 प्रतिशत तथा कटिहार के बारसोई प्रखण्ड में 16.33 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी। बांगलादेश से हो रही घुसपैठ के कारण बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जिले तो मुस्लिम बहुल हो गए हैं। बिहार का किशनगंज जिला भी मुस्लिम बहुल हो गया है और निकट भूतिष्ठ में कटिहार तथा अररिया भी मुस्लिम बहुल हो जाएंगे। पूर्वोत्तर जाने वाली ट्रेनें झारखण्ड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार और किशनगंज जिले से होकर ही गृजरी हैं। जिहादी ताकतें बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार, झारखण्ड के साहिबगंज और पाकुड़ तथा बंगाल के मुर्शिदाबाद-मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जिले को भारत से काटने की एक दीर्घकालिक योजना पर कार्यरत हैं।

साकार होता स्वामी विवेकानंद का सपना, उनके ही विचारों से ओतप्रोत हैं पीएम मोदी द्वारा प्रवर्तित पांचों संकल्प

संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार 1984 को 'अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष' घोषित किया गया। इसके महत्व पर विचार करते हुए भारत सरकार ने दोनों दिनों (20 और 21 जून) को 'नया भारत निकल पड़े मोरी' की दुकान से, भड़भूंजे के भाइ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झापड़ियों से, जंगलों से, जी ने उत्तर दिया कि 'गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। अगले 50 वर्षों तक सिर्फ भारत को गुलामी से आजाद करना ही तुम्हारा धर्म

न धारणा का। इक 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जन्म-जयंती के दिन को 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। वस्तुतः, स्वामी विवेकानंद वह विश्वव्यापी विचार है, जिसे न सिर्फ भारत, अपितु विश्व के युवाओं ने भी स्वीकार किया है। 'नर सेवा-नारायण सेवा' का मंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद की आज 160वीं जन्म-जयंती है। उन्होंने 39 वर्ष पांच माह और 22 दिन का जीवन जिया, लेकिन उनके संसार से जाने के लगभग 120 वर्ष बाद भी न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व उन्हें एक प्रेरणा के रूप में याद कर रहा है। भारतीय आन्मा को अक्षण्ण रखते हुए सार्वभौमिक विचारों से संवाद स्वामी जी की प्रमुख विशेषता रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 'भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, जो पूरे संसार का पथप्रदर्शन करने में समर्थ होगा।' उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी अब सिर्फ उसका सत्य सिद्ध होना शेष है। वर्तमान भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमें यह आशा है कि हमें

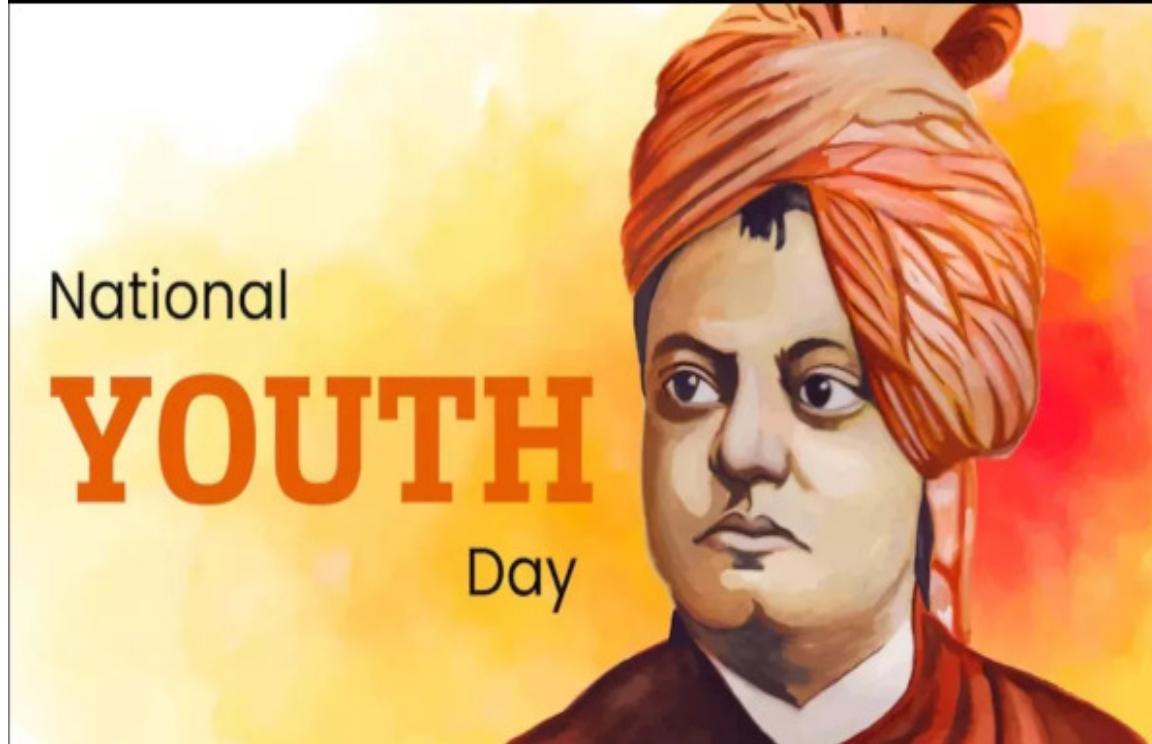
पहाड़ों से, पर्वतों से और खेत-खलिहानों से और पुनः भारत मां को विश्वगुरु के पद पर आसीन कर दे।' पीएम मोदी का भी यही मानना है कि जनभागीदारी और 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र से ही हम विकसित भारत के महान लक्ष्य को पूरा करेंगे। दूसरा संकल्प है 'गुलामी से मुक्ति'। 1897 में स्वामी विवेकानन्द से किसी ने पूछा कि 'स्वामी जी मेरा धर्म क्या है?' स्वामी है।' स्वामी जी कहा करते थे कि ठहम वह हैं, जो हमें हमारे सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। ठ अर्थात् अपने मन मस्तिष्क में गुलामी का कोई भी विचार न रहने दें। यही बात पीएम मोदी ने कही कि हमारे मन के भीतर किसी भी कोने में गुलामी का एक भी अंश न रहे।

तीसरा संकल्प है विरासत पर गर्व।
11 सितंबर, 1893 का स्वामी जी
का शिकागो में दिया गया भाषण
इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब

विश्व वि
भारतव
लहर दौ
वैभव व

विश्व विजय की इस यात्रा से सभी भारतवासियों में ऊर्जा की एक नई लहर दौड़ी और भारत किर से परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में

विनाश नहीं, संवाद। मतविरोध नहीं, समन्वय और शांति।' आज विश्व को आतंकवाद के खिलाफ नरेन्द्र मोदी का भी यही संदेश है। स्वामी विवेकानन्द ने देशवासियों से कहा था कि 'इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और अभिमान के साथ यह घोषणा करो कि हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है।' प्रधानमंत्री मोदी ने भी 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के भाव को मन में समेटे हुए कहा है कि हमें अपनी देश की विविधता को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की एकता और एकजुटता में ही होती है। पांचवां संकल्प है 'नागरिकों का कर्तव्य'। स्वामी विवेकानन्द द्वारा लिखित 'कर्मयोग' नामक पुस्तक का चौथा अध्याय है- 'कर्तव्य क्या है?' इसमें उन्होंने जीवन के हर कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया है। स्वामी जी ने लिखा है कि 'हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने प्रति धृणा न करें।' उसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कर्तव्य देश और समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है। यह मूलभूत प्रणाली है। स्पष्ट है भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल के संकल्पों में स्वामी विवेकानन्द के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति, गौरवपूर्ण संस्कृति-संस्कारों से ओतप्रोत अद्भुत सामर्थ्य, वैश्विक शांति एवं सौहार्द के लिए वसुधैव कुटुंबकम् के भारतीय दर्शन और मानव कल्याण की प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म के कारण ही भारत विश्वगुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा।



विकासशील देशों की

विकसित देशों ने संसाधनों के मामले में विकासशील देशों के साथ पारंपरिक रूप से अन्याय ही किया है। इसने दुनिया के इन दोनों ध्रुवों के बीच असमानता की खाई को चौड़ा किया है। दिसंबर में साउथ सेंटर द्वारा जारी 'इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज एंड स्टोलन असेट रिकवरी' अध्ययन में पुनः इसी रुक्षान की पुष्टि हुई है। ऐसे में विकासशील देशों के हितों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरवी अपरिहार्य हो गई है। इसी दायित्व की पूर्ति के लिए भारत 12 जनवरी से दो दिवसीय 'वाइस आफ ग्लोबल साउथ समिट' का आयोजन करने जा रहा है। इसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जुटकर एक मंच पर अपना दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं का साझा करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विकासशील देशों में सहयोग एवं एकता का भाव बढ़ाना है। भारत हमेशा से विकासशील देशों की आवाज को मुखरता से उठाने के मामले में अग्रणी रहा है। असल में वैश्विक समुदाय में भारत की स्थिति बहुत अनोखी है। विकासशील देशों में गिनती होने के बावजूद भारत विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय संबंधों विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश मिल जाती है। संप्रति भारत कम से कम तीन स्तरों पर विकासशील देशों की चिंताओं को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है। जैसे कि मौजूदा सरकार के दौर में भारत ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर सक्रियता से सहभागिता आरंभ की है। फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हो या जी-20 की कमान, भारत ने समय के साथ एक नेतृत्वकर्ता का अवतार लिया है। वह विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक सहित तमाम मंचों पर विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है। दूसरा स्तर विकासशील देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने का है। गत वर्षों के दौरान भारत ने तमाम विकासशील देशों विशेषकर अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आधार पर मजबूत रिश्ते गांठे हैं। इससे विकासशील विश्व के हितों के पक्ष में माहौल बनाने का उपयुक्त मंच तैयार हुआ है। तीसरा पहलू दक्षिण-दक्षिण

स्वीकृति दौर में f रोधी वै दक्षिण-भारत है। दुनिंहे देश ही देशों या करते हैं चीन 3% अन्य देविस्तार कर्ज के कुख्यात जाल में देशों की गली f आर्थिक इस्तेमाल परियोजन देशों के

स्वीकृति प्रदान की थी। हाल के दौर में विकासशील देशों को कोविड रोधी वैक्सीन उपलब्ध कराना भी दिक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। दुनिया में चुनिंदा विकासशील देश ही हैं, जो अन्य विकासशील देशों या अल्पविकसित देशों में निवेश करते हैं। इस प्रकार के निवेश में चीन और भारत अग्रणी हैं, जो अन्य देशों में भी विकास कार्यों को विस्तार दे रहे हैं। हालांकि, चीन कर्ज के जाल में फंसने के लिए कुख्यात हो चला है। चीन की कर्ज जाल में फंसने वाली रणनीति कई देशों की संप्रभुता पर आघात करने वाली सिद्ध हुई है। चीन अपनी आर्थिक एवं वित्तीय ताकत का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे से ज़ड़ी परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को कर्ज की आड़ में लुभाता है और फिर जब वह देश उसके इस जाल में फंस जाता है तो इसका परिणाम वहां चीन के राजनीतिक प्रभाव एवं रणनीतिक लाभ के रूप में निकलता है। इस चीनी परिपाटी को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी है कि इससे आर्थिक अस्थिरता और यहां तक कर्जदार देशों के समक्ष दिवालिया होने तक का संकट पनप सकता है। पड़ोस में श्रीलंका और पाकिस्तान ही इस चीनी कर्ज जाल में फंसने के भूतक्षेपी हैं। इसी के चलते श्रीलंका बैनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लौज पर देने को विवश हुआ। पाकिस्तान ने भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के लिए बींजिंग से भारी-भरकम कर्ज लिया है और यही आशंका जताई जा रही है कि उसके लिए उसकी भरपाई बेहद कठिन होगी।

युनौतियों से जूझते लोकतंत्र, बाजील का घटनाक्रम अन्य के लिए भी एक सबक

बीते दिनों ब्राजील की संसद यानी कांग्रेस में उपद्रव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे पहले कड़वाहट भरे चुनाव अभियान के करीब दो महीने बाद माझी अंतर से बनी सरकार के दौर में ब्राजील में चीजें सहज होती दिख रही थीं। इस महीने जब लुइस इनसियो 'लूला' डी सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति की स्थपथ ली तो उन्होंने 'लोगों के साथ मिलकर' ब्राजील के 'नर्मिण' का वादा किया था। साथ ही उन्होंने अपने पूर्ववर्ती और प्रतिद्वंद्वी जोड़स बोलसोनारो पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि हम उन लोगों के विरुद्ध प्रतिशोध का कोई भाव नहीं रखते, जिन्होंने देश पर अपना निजी और वैचारिक एजेंडे थोपने का प्रयास किया। लूला ने कहा कि हम विधि के शासन की सत्ता सुनिश्चित करेंगे। उस समय बोलसोनारो के समर्थकों की ओर से हिंसा की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि, तब ऐसा कुछ घटित नहीं हआ, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति साबित हुई। लूला के शपथ ग्रहण के करीब हफ्ते भर बाद बोलसोनारो समर्थकों ने ब्राजीली झंडा थामकर राजधानी ब्राजीलिया स्थित संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आवास जैसे लोकतांत्रिक प्रतीकों पर धाव बोल दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि सरकार को महत्वपूर्ण स्थल 24 घंटों के लिए बंद करने पड़े। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को तैनात करना पड़ा। लूला ने प्रदर्शनकारियों के संसद तक पहुंचने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आडे हाथों लिया। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में ब्राजीलिया के पूर्व जन सुरक्षा प्रमुख एंडरसन टोरेस भी शामिल थे। इस घटनाक्रम ने ब्राजील के अस्थिर लोकतांत्रिक ढांचे को दर्शने का ही काम किया। इस पूरे फसाद की जड़ अक्टूबर में हुए तत्त्व चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसने देश का इतना शूरीकरण कर दिया कि यह देश उससे उजें संकट को सुलझा नहीं सका। बेहद करीबी मुकाबले में लूला ने 50.8 प्रतिशत मतों के साथ सत्ता हासिल की तो उनके प्रतिद्वंद्वी को 49.2 प्रतिशत मत मिले। ब्राजील के इतिहास में यह सर्वाधिक शूरीकरण वाला चुनाव सिद्ध हुआ, लेकिन बोलसोनारो ने कभी आधिकारिक रूप से हार स्वीकार नहीं की। वह मतदान प्रणाली को लेकर भी संदेह प्रकट कर चुके हैं। उनके तमाम समर्थकों को भी उनकी हार गले नहीं उत्तर पाई और उन्हें लगा कि चुनावों में गड़बड़ी हुई। ब्राजील में वाम और दक्षिण के बीच विभाजन देखना

बहुत सरल है, किंतु आज बुनियादी
भ्रंशरेखा यही दिखाती है कि ब्राजील
की तक्रीबन्न आधी आबादी लग

पुनर्स्थापित करने का श्रेय देते हैं। नेतृत्व ने इस विभाजन की खार्फ को और चौड़ा दी किया। यह तो

ने इसे भड़काया। अनुमान से कहीं ज्यादा करीबी चुनाव परिणाम ने कई तर्गीं में उस धूरणा को मजबूत

माध्यम से ब्र
को और बढ़ा
यह हाजीली

शासनों में ऐसा ज़ड़ाव नहीं होता और वहां एक सुगौंठित नौकरशाही सब काढ़ प्रबंध करने में पर्याप्त होती

की जीत से प्रभावित नहीं और उनकी सोच यही है कि ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। बात व्यापक सांस्कृतिक विभाजन तक पहुंच गई है, जहां बोल्सोनारो के तमाम समर्थक उन्हें 'ईश्वर, मातृभूमि और परिवर्ता' जैसे मूल्यों को बोलसोनारो ने दंगाइयों की निंदा की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को भड़काने की जिम्मेदारी नहीं ली और पूरे प्रकरण में सार्वजनिक रूप से सामने आने में भी छह घंटे लगा दिए। लूला ने बोलसोनारो पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि पूरे राष्ट्रपीत के तमाम भाषणों के किया कि लूला की जीत में कुछ न कुछ गड़बड़ है और उसे दुरुस्त करने के लिए किसी भी हाद तक कुछ भी किया जाना चाहिए। इस प्रकरण ने दो वर्ष पहले ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद में किए गए उपद्रव की यादें ताज़ा करा दी। ट्रंप के कुछ समर्थकों की भी अफवाहों के

समीक्षा का समय है। संस्थान स्वाभाविक रूप से नाज़क होते हैं। उनकी निरंतर निगरानी आवश्यक होती है। कारगर बने रहने के लिहाज से राजनीतिक लोकतंत्र सबसे कठिन संस्थागत ढांचा होता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। तानाशाही

है। चीनी कम्प्युनिस्ट पार्टी ऐसी नौकरशाही की सबसे बड़ी मिसाल है, जो समय के साथ और प्रभावी होती गई, किन्तु लोकतंत्र और उसके संस्थान कहीं मैनहनत की मांग करते हैं। उन्हें भरोसे के मानवीय मूल्यों, आस्था-विश्वास और दायित्व भाव के साथ पौष्ठिक करना पड़ता है।

